

अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधार कार्ड होने पर ही राशन कार्ड धारकों को अनाज मिलेगा 3.5 करोड़ राशन कार्डों में 1.5 करोड़ फर्जी!

राज्य मुख्यालय | शोभित मिश्र

शहरी क्षेत्रों के बाद अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधार कार्ड होने पर राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न मिलेगा। इसके लिए ग्रामीण इलाकों की 67 हजार राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनें लगाने जा रही हैं। आधार कार्ड से लिंक इन मशीनों में राशन कार्डधारक को अंगूठा लगाने के बाद राशन मिलेगा। इस नई तकनीकी से राशन वितरण व्यवस्था संचालित होने के बाद करीब साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण इलाकों के राशन कार्ड धारकों में से करीब डेढ़ करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारक पाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ग्रामीण इलाकों की राशन की दुकानों में ई-पॉस मशीनें लगाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलते ही इस साल जून तक ग्रामीण

क्षेत्रों की राशन की दुकानों में ये मशीनें लगा दी जाएंगी।

शहरी क्षेत्र में डेढ़ लाख निकले फर्जी राशन कार्ड धारक : शहरी क्षेत्र की तीन हजार राशन की दुकानों पर 60 लाख राशन कार्डधारक पिछले चार महीने पहले तक राशन पा रहे थे। ई-पॉस मशीनों में पात्र व्यक्ति ही राशन पा सकता है। ऐसे में शहरी इलाकों की राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाने पर डेढ़ लाख राशन कार्ड धारक फर्जी पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि इसी अनुपात में ग्रामीण इलाकों में भी ई-पॉस मशीनें लगते ही 3.5 करोड़ राशनकार्ड धारकों में से 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारक फर्जी निकलने का अंदाजा है।

मशीनों पर केंद्र व राज्य का अंशदान
ग्रामीण इलाकों की 67 हजार राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाए पर 17 प्रति कुन्तल खाद्यान्न के हिसाब से केन्द्र और

ई-पॉस मशीनों को शहरी क्षेत्र में लगाने का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। इस प्रणाली के शुरू होने से शहरी क्षेत्र के 70 फीसदी राशन कार्ड धारक राशन पाने लगे हैं। जल्द ही सभी जायज राशन कार्ड धारक इन मशीनों पर अंगूठा लगाते ही राशन पाने लगे।
-आलोक कुमार, खाद्य एवं रसद आयुक्त

राज्य सरकार अपना अंशदान देगी। इनमें से साढ़े आठ रुपए प्रति कुन्तल केन्द्र का बाकी हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। इन मशीनों को लगाने का ठेका निजी एजेन्सी को दिया जाएगा। ये एजेन्सी अपना कॉल सेन्टर बनाकर राशन की दुकान में लगी मशीनों का रखरखाव और उन्हें बदलने का भी काम करेगी। इस तरह सालाना करीब 100 करोड़ इन मशीनों के रखरखाव में खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।